प्रदेश के सांसदों ने भी इस बात को महसूस किया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया जनपद से यदि अपराधों को कम करना है तो वहां निश्चय ही बहुत बड़ी कोई एक औद्योगिक इकाई लगानी चाहिए। कागज का कारखाना भी यहां चल सकता है। खाद का कारखाना लगाने की बात चल रही थी, एल्युमिनियम का भी कारखाना यहां बनाने की बात प्रकाश में आई, किन्तु केवल लोक सभा में और लोकसभा के बाहर चर्चा ही चली कोईकार्यवाही नहीं हुई।

ऐसी स्थिति में माननीय उद्योग मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वह कृपया मेरे संसदीय क्षेत्र सैदपुर की बिगड़ी हुई स्थिति को देखें। वहां अविलम्ब कोई बड़ा उद्योग केन्द्र सरकार के बजट से स्थापित कराने की व्यवस्था करें। यदि शीघ्र कोई उद्योग लग सकता है तो पढ़े लिखे एवं अनपढ़ हज़ारों लोगों को रोजगार मिलेगा। निश्चय ही लोग अपने यहां काम करेंगे बेकारी दूर होगी, अपराध खत्म होंगे। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर अवश्य ध्यान देने की कृपा करेंगे।

(v) HISSAR TEXTILE MILL.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Sir, more than 5000 workers of the Hissar Textile Mill, Haryana, have been rendered out of work as a result of the lockout declared by the management on 30th March, 1983, for an indefinite period. Sir, the owners, who are one of the biggest monopoly houses in the country have been following anti-labour policies for a long time, for which the workers were forced to go into a prolonged strike for 108 days in 1981, At that time the Chief Minister of Haryana brought about a settlement on May 8, 1981, in which it was decided that the quantum of D. A. entitlement of the workers will be finalised bilaterally within three months. The management, however, refused to settle the issue during the past two years. On the other hand, they dismissed 30 workers, suspended another 50 and issued charge sheets against hundreds of workers in order to terrorise them. The workers while agitating for a settlement approached the Labours Ministry of Haryana for intervention. The Ministry had fixed April 4 as the date for conciliation. The management instead of seeking a settlemeat has imposed this lockout violating various sections of Industrial Disputes Act.

Sir, indiscriminate flouting of labour laws by the owners of various Industries has become the order of the day. Therefore, I urge that the Government should immediately intervene for opening of the Mill and start immediate drosecution of the management if they refuse to do so.

(vi) FACILITES TO WORKERS ENGAGING IN BIDI MANUFACTURING IN MADHYA PRADESH

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अकेले मध्य प्रदेश के लगभग पांच लाख मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं तथा प्रमुख रूप से यह काम जबलपुर, दमोह तथा सागर ज़िलों में अधिक होता है। लगभग 25 लाख जनता की रोजी रोटी इस बीड़ी मज़दूरी से जुड़ी है।

इन मज़दूरों का शोषण लगातार; बहुत बड़े प्रमाण में बीड़ी कारखानों के मालिक करते हैं। उदाहरणार्थ, बीड़ी बनवाई की दर प्रति हजार 7.8711 पैसा शासन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात भी मज़दूरों को पांच रुपये से अधिक नहीं मिलती, परन्तु खातों में पूरा रेट बताया जाता है।

केन्द्रीय कानून बीड़ी वर्क्स वैलफेयर फण्ड 1978 के नियम 41 के अन्तर्गत घरखाता व कारखाना खाता, बीड़ी श्रमिक को परिचय पत्र (आइडैंटिटी कार्ड) देने का प्रावधान है, परन्तु बीड़ी कारखाना मालिक इस पर अमल नहीं कर रहे हैं।

प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 के अन्तर्गत महिला बीड़ी श्रमिकों को प्रसूति लाभ न देने पड़ें, इस लिए महिला बीड़ी श्रमिकों के नाम बीड़ी कारखाने के मालिक नहीं लिखाते। लगभग 30 प्रतिशत महिलायें बीड़ी श्रमिक का काम करती हैं। लगातार कई वर्षों से बीड़ी बनाने के बाद भी इन श्रमिक महिलाओं के नाम खाते बदल दिये जाते हैं। जिसके द्वारा शासन द्वारा संचालित कल्याण कारी योजनाओं व अन्य कानूनी अधिकारों का लाभ उन्हें न मिज सके।

बीड़ी बनाने के लिए जो तम्बाकू श्रमिकों को दी जाती है, उस पर केन्द्रीय आबकारी विभाग की दखल रहती है। लगभग दस रुपये किलो वाली तम्बाकू इन श्रमिकों द्वारा यदि बीड़ी बनाने ज घटती है, तो 50 से 90 रु० किलो तक इसकी कीमत श्रमिकों से वसूल की की जाती है तथा यह राशि पूर्ण रूपेण बीड़ी कारखानेदार हड़प जाते हैं।

अतः केन्द्र शासन से मांग की जाती है कि बीड़ी कारखानेदारों से निम्नलिखित बातों पर बीड़ी श्रमिक को राहत दिलवाई जाए :

1. बीड़ी मजदूरों को प्रति हजार 7.811 रेट मिले।
2. बीड़ी मजदूर को परिचय पत्र (आई-डेंटिटी कार्ड) दिया जाए।
3. बीड़ी महिला श्रभिकों को प्रसूति लाभ अधिनियम का लाभ दिया जाए।
4. बीड़ी श्रमिकों से जो तम्बाकू की कीमत नाजायज ढंग से वसूल की जाती है, वह बन्द की जाए।

(vii) LINKING GANGA CAVERI FOR SOLVING IRRIGATION PROBLEMS IN TAMIL NADU

SHRI ERA ANBARASU (Chengalpattu) : I make the following statement under Rule 377 :

India is essentially an agricultural country depending on the annual seasonal rains. Unfortunately, we cannot resort to any permanent long-term projects to combat the vagaries of nature at times of floods and drought in the country. We know at present Tamil Nadu, Karnataka, Andhra-Pradesh, Kerala, Orissa and West Bengal are very badly hit by drought situation.

I thank the Prime Minister of India on this occasion for her surprise visit to Tamil Nadu for on the spot study of the drought conditions in Tamil Nadu and for her kind gesture in providing a sum of Rs. 10 crores and food-grains as an interm drought relief.

Even in the central Budget a sum of Rs. 750 crores hav been earmarked for this purpose. This is only a temporary relief measure most of which do as not fully reach the needy people. In order to provide a permanent relief from these annual calamities on long-term perspective plan, the linking of Ganga Kaveri rivers will be a proper solution. The Government of India can approach the world Bank for the resources for executing this massive project. The Government of India can deploy our defence forces also in this project.

Linking of Ganga Kaveri rivers will help to establish a bridge between the people of the North and the South by means of cultural ties and contacts, coexistence, trade and commerce trade links etc. by sweet and sanguine. Ganga waters and not of salt water,

This project will serve the purpose of irrigation, power generation and meeting the scarcities of drinking water at the national level. The surplus water will be stored and shortages will be met. If this project comes into force, the language and culture of North will fast move towards the South and VICE-VERSA along with the flow of sanguine Ganga waters from North to South.

Hence, I draw the attention of the Hon, ble Minister for Agriculture and Irrigation to examine the feasibilities of this project, giving top-priority and submit a comprehensive report to this august House. I wish the hon. Minister at least to accept this project in principle.